भारत सरकार

आवासन और शहरी कार्य मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न सं.1839

05 दिसंबर, 2024 को उत्तर दिए जाने के लिए

अमृत के तहत पहल

1839. डॉ. कडियम काव्य:

क्या **आवासन और शहरी कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या सरकार ने विगत तीन वर्षों के दौरान हाशिए पर पड़े समुदायों की आवश्यकताओं को पूरा करने तथा झुग्गी-झोपड़ियों और निम्न आय वाले इलाकों में बुनियादी सेवाएं और अवसंरचना उपलब्ध कराने के लिए अटल कायाकल्प और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) के अंतर्गत पहल शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्य-वार, जिला-वार और वर्ष-वार ब्यौरा क्या है, यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार के पास सतत शहरी विकास के लिए अमृत परियोजनाओं में स्मार्ट सिटी अवधारणाओं और प्रौद्योगिकियों को एकीकृत करने की कोई योजना है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

आवासन और शहरी कार्य राज्य मंत्री

(श्री तोखन साहू)

(क) से (घ): 25 जून 2015 को देशभर के चयनित 500 शहरों (15 शहरों के विलय सहित 485 शहर) और कस्बों में 1 लाख करोड़ रु. के परिव्यय के साथ अटल नवीकरण और शहरी परिवर्तन मिशन (अमृत) शुरू किया गया था। मिशन का उद्देश्य चयनित शहरों और कस्बों में जलापूर्ति, सीवरेज और सेप्टेज प्रबंधन, वर्षा जल निकासी, हरित क्षेत्र और पार्क तथा गैर-मोटर चालित शहरी परिवहन के क्षेत्रों में इन्फ्रास्ट्रक्चर का विकास करना है ।

अमृत के अंतर्गत शहर में स्लम-क्षेत्र और कम आय वर्ग सहित दिशा-निर्देशों के व्यापक ढांचे के अनुरूप परियोजनाओं को डिजाइन करने, प्राथमिकता देने और कार्यान्वित करने का अधिकार राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (यूटी) को है। अमृत के अंतर्गत अनुमोदित परियोजनाओं की राज्यवार संख्या अनुलग्नक में दी गई है।

स्मार्ट एलिमेंट, घटक और प्रौद्योगिकियाँ अमृत परियोजनाओं का हिस्सा हैं और इसका उद्देश्य स्थायी शहरी विकास को बढ़ावा देना है। अमृत दिशा-निर्देशों में जल आपूर्ति और सीवरेज परियोजनाओं के हिस्से के रूप में पर्यवेक्षी नियंत्रण और डेटा अधिग्रहण (एससीएडीए) जैसे स्मार्ट एलिमेंट का प्रावधान किया गया है। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार 230 जल आपूर्ति परियोजनाएं और 146 सीवरेज परियोजनाएं एससीएडीए के तहत कार्यान्वित की जा चुकी हैं।

***

"अमृत के तहत पहल" के संबंध में दिनांक 05.12.2024 को उत्तर हेतु अतारांकित प्रश्न संख्या 1839 के भाग (क) से (घ) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक।

निर्माणाधीन अमृत परियोजनाओं की राज्यवार स्थिति

(राशि करोड़ रुपये में)

क्र. सं.	राज्य	कुल	
		सं	परियोजना लागत (करोड़ रुपए में)
1	अंडमान व निकोबार द्वीप समूह	79	10.90
2	आंध्र प्रदेश	226	3333.76
3	अरुणाचल प्रदेश	11	129.81
4	असम	17	625.71
5	बिहार	65	2575.72
6	चंडीगढ़	12	57.41
7	छत्तीसगढ	293	2269.50
8	दादरा और नगर हवेली	2	41.45
	दमन और दीव	3	25.98
9	दिल्ली	26	674.77
10	गोवा	15	259.98
11	गुजरात	451	5165.96
12	हरियाणा	136	2919.99
13	हिमाचल प्रदेश	75	304.51
14	जम्मू और कश्मीर	84	527.99
15	झारखंड	59	1615.06
16	कर्नाटक	407	5118.95
17	केरल	1111	2538.74
18	लद्दाख	20	72.02
19	लक्षद्वीप	6	2.42
20	मध्य प्रदेश	216	6765.91
21	महाराष्ट्र	207	8011.32
22	मणिपुर	6	211.87
23	मेघालय	15	81.65
24	मिजोरम	15	136.58
25	नागालैंड	27	126.96
26	ओडिशा	191	1714.42
27	पुदुचेरी	23	64.10
28	पंजाब	163	2761.02
29	राजस्थान	144	3548.32
30	सिक्किम	75	37.53
31	तमिलनाडु	445	13339.43
32	तेलंगाना	66	1663.08
33	त्रिपुरा	10	160.28
34	उत्तर प्रदेश	670	11838.07
35	उत्तराखंड	151	592.97
36	पश्चिम बंगाल	473	4050.25
	कुल	**5995**	**83374.39**